मैनेज बुलेटिन

राष्ट्रियकृषि विस्तार प्रबंधसंस्थान से **मार्च-अप्रैल 2014**

कृषि में मोबाइल पर आधारित ई-विस्तार सेवाएँ राष्ट्रीय कार्यशाला

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सामग्री पेश करने वाले वेब पोर्टल तक पहुँचने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी कमजोर है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल की पहुंच में सुधार हुआ है और मोबाइल हैंडसेट की कीमतों में तेजी से कमी आई है। मोबाइल आधारित ई-विस्तार सेवाएं किसानों को कृषि पद्धतियों पर विषय विशेषज्ञों/विशेषज्ञों द्वारा सलाह उपलब्ध कराने में मददगार हो सकती हैं।

ई-विस्तार आधारित मोबाइल की उभरती भूमिका को देखते हुए, मैनेज में 27 से 28 मार्च, 2014 तक "कृषि में मोबाइल आधारित ई-विस्तार सेवाएँ" एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य था - मोबाइल की पहल पर किसानों के लिए मोबाइल की पहल पर आधारित सेवा वितरण पर राष्ट्रीय अनुभवों से प्राप्त सीख को मजबूत और साझा करना; बुनियादी स्तर पर श्रेष्ठ अभ्यास साझा करना और क्षेत्र से व्यवसायी तथा विशेषज्ञों के मध्य ज्ञान साझा करने की सुविधा; किसानों के लिए सामग्री की विशिष्ट आवश्यकताओं का विश्लेषण जिसे मोबाइल सक्षम कृषि सेवाओं के माध्यम से सही दिशा दी जा सके; कृषक समुदाय में मोबाइल आधारित ई-विस्तार सेवाओं की अवधारणा को बढ़ावा देना; ज्ञान का अंतर मिटाने तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में कृषि सूचना के आधार पर मोबाइल आधारित सेवा प्रदान करने के लाभों के लिए रणनीति तैयार करना; गुणवत्ता, विश्वसनीयता और किसानों को उनके मोबाइल फोन पर कृषि के गठन की समय पर उपलब्धता में सुधार के लिए विभिन्न स्तरों पर हस्तक्षेप के संभावित क्षेत्रों का सुझाव।

एनआईसी-हैदराबाद, आईआईआईटी हैदराबाद, डीआरआर, सीडैक, इक्रीसैट और मैनेज से महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने आईसीटी अनुप्रयोगों में अपने अनुभव बाँटे। मैनेज द्वारा विकसित वीडियो आधारित सलाहकार सेवाओं के मॉडल भी पेश किये गये। यह सुझाव दिया गया कि उन्ही अनुप्रयोगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिसमें किसानों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं प्रदान मोबाइल पर आसानी से वहनीय हों। खेत सलाहकार, बाजार कीमत, मौसम की जानकारी, योजनाओं और सब्सिडी की जानकारी जैसी मोबाइल आधारित विस्तार सेवाएं मोबाइल के माध्यम से उपलब्ध करवाना। सलाहकार सेवाओं के लिए किसानों

और विशेषज्ञों के बीच सीधी बातचीत को स्मार्ट फोन पर उपलब्ध कनेक्टिविटी से भी लाइव वीडियो विकसित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

शैक्षिकसमिति की बैठक

मैनेज के महानिदेशक श्री. बी. श्रीनिवास, आईएएस, की अध्यक्षता में मैनेज शैक्षिक समिति की 18 वीं बैठक 22 मार्च 2014 को आयोजित की गई। समिति ने अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 तक की अवधि के दौरान की मैनेज की शैक्षिक गतिविधियों की समीक्षा की। समिति ने 2014-15 के शैक्षिक कैलेंडर पर चर्चा की और मंजूरी भी दी।

वर्ष 2014-15 के लिए कुल 196 प्रशिक्षण कार्यक्रमों और 12 राष्ट्रीय कार्यशालाओं की योजना बनाई गई है। समस्या सुलझाने के दृष्टिकोण को 20% प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपनाया जाएगा। समिति ने 2014-15 के लिए शोध प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए एक विस्तार मैनुअल तैयार करना; कृषि और संबद्ध विभागों के विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए ई-ट्रेनिंग आवश्यक विश्लेषण (ई-टीएनए) का डिजाइन और विकास; कृषि विपणन के आधुनिक साधन अपनाने में नियमित बाजार की भूमिका - एक तुलनात्मक अध्ययन; संबद्ध क्षेत्रों में एक्सटेंशन के विश्लेषण से प्रयास; पीपीपी मोड पर कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण युवाओं में कृषिउद्यम विकास; कृषि उत्पादों के विपणन के लिए 'महिला समूहों द्वारा अपनायी नवरीति; एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के लिए समवर्ती निगरानी और अध्ययन प्रणाली का प्रारूप और विकास।

शहरी कृषि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

शहरी कृषि एक गतिशील अवधारणा है जिसमें कृषि के वाणिज्यीकरण के लिए घरेलू स्तर पर विभिन्न प्रकार की खेती प्रणाली एवं जीविका के उत्पाद और संसाधन शामिल हैं। यह विविध संसाधन स्थितियों के भीतर मौजूद होता है। शहरी कृषि इस प्रकार विभिन्न शहरों में अलग-अलग रूप लेती है; यह सड़क, रेलवे के किनारे स्थित भूमि, छतों और बालकनियों पर, शहर के पिछवाड़े या खुले स्थानों आदि में हो

सकती है। इसमें विभिन्न हितधारक भी शामिल हैं, अर्थात् व्यक्तिगत उत्पादक, उद्यमी, समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ), गैर सरकारी संगठन, राष्ट्रीय या विकास और शहरी कृषि को बढ़ावा देने में स्थानीय सरकारों और अनुसंधान संस्थान।

शहरी कृषि में महत्व, मुद्दों, क्षमता और आयामों को ध्यान में रखते हुए, शहरी कृषि पर 17-21 मार्च, 2014 के दौरान एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय संदर्भ में शहरी कृषि को बढ़ावा देने की अवधारणा और आवश्यकता पर विचार करना; शहरी कृषि की हिस्सेदारी और दस्तावेज़ अनुभव; शहरी कृषि को बढ़ावा आवश्यक योजना, संगठन और प्रबंधन प्रणाली पर चर्चा; शहरी कृषि की अवधारणा और संचालन को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना का विकास। मॉड्यूलों में खाद्य हरियाली, हरित गृह किट, शहरी पशुपालन, शहरी क्षेत्रों में सजावटी मछली पालन, छत के ऊपर बागवानी, शहरी अपशिष्ट प्रबंधन आदि शामिल हैं। इसमें कुल 15 प्रतिभागि थे।

कृषिउद्यम विकास पर सहयोगात्मक कार्यक्रम

"कॉनसेर्टियम मोड के माध्यम से ग्रामीम युवाओँ में कृषिउद्यम विकास" पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम अप्रैल, 2014 में मध्य प्रदेश के केसला में शुरू किया गया। यह सिंजेन्टा फाउंडेशन भारत, प्रदान, मैनेज, स्मार्ट स्टैप और आईडीबीआई बैंक का एक सहयोगात्मक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण युवाओँ को कृषिउद्यमी में परिवर्तित करना था, जो किसानों को अतिरिक्त विस्तार सेवाएं प्रदान कर सकें। सिंजेन्टा फाउंडेशन भारत संघ, मैनेज क्षमता निर्माण सहायता, स्मार्ट कदम, हैंडहोल्डिग सहायता, आईडीबीआई बैंक द्वारा कृषिउद्यमियों को ऋण तथा किसानों सेवा क्षेत्र और प्रदान नेटवर्क के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किये जाने की अगुवाई करता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से लगभग 29 सामुदायिक सेवा प्रदाताओं ने भाग लिया।

एसी और एबीसी - एक अद्यतन

एग्री क्लीनिक एवं कृषि व्यवसाय केन्द्र योजना के तहत चुनिंदा पेशेवर कृषकों को कृषि उद्यमिता स्थापित करने के लिए हैंड होल्डिंग समर्थन के साथ कृषि उद्यमिता में प्रशिक्षण दिया जाता है।

2013-14 के दौरान, कुल 4668 आवेदन प्रप्त हुए, 4451 उम्मीदवारों ने नोडल प्रशिक्षण संस्थानों (NTIS) में प्रशिक्षण प्राप्त किया और 2320 कृषिउद्यम स्थापित किए गए। इस प्रकार 21 राज्यों में 52.12% की सफलता दर को प्राप्त की गई।

पीजीडीएइएम ई-अध्ययन संसाधन

कृषि विस्तार प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDAEM), सेवारत विस्तार कार्यकर्ताओं के ज्ञान और तकनीकी प्रबंधकीय क्षमता को उन्नत करने के लिए दूरस्थ शिक्षा मोड पर शुरू किया। उम्मीद्वारों के लिए अध्ययन की मुद्रित सामग्री भेजी जाती है और यह ऑनलाइन भी उपलब्ध है।
इस वर्ष से ई-अध्ययन संसाधनों की (पूर्व-रिकार्ड की गई डीवीडी मॉड्यूल) संशोधित अध्यापन के भाग के रूप में शुरुआत की गई।

पाइप लाइन में

सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से आईटी सक्षम कृषि सेवाएँ

सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) ग्रामीण जनता को उनके गांवों में नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है। मंत्रालय ने अब तक देश में लगभग एक लाख सीएससी स्थापित किये हैं। प्रत्येक सीएससी लगभग छह गांवों को सेवाएं प्रदान करता है। नागरिकों के लिए सरकार को बिल के भुगतान करने जैसी उपयोगिता सेवाएं निशुल्क हैं, लेकिन सरकार से नागरिकों को (जी2सी) अन्य सेवाएं शुल्क आधारित हैं। सीएससी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वेब सक्षम ई गवर्नेन्स सेवाओं में आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र, और बिजली, टेलीफोन और पानी के बिल के रूप में उपयोगिता भुगतान, ग्रामीण बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और प्रशिक्षण, डीटीपी, मुद्रण और इंटरनेट ब्राउज़िंग शामिल हैं।

उपर्युक्त नागरिक सेवाओं के अलावा, सीएससी दिशा निर्देश में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में सामग्री और सेवाओं की विस्तृत विविधता प्रस्तुत करने पर भी विचार किया गया है। लेकिन, वास्तव में, इन क्षेत्रों में सेवाएं एक सेवा अर्थात् किसानों के भूमि रिकार्ड को छोड़कर न्यूनतम हैं। किसानों को आदानों की उपलब्धता, विपणन के अवसरों , सलाहकार समर्थन और विशेष रूप से राज्य विभागों द्वारा की पेश की जाने वाली विभिन्न योजनाओं की सब्सिडी का लाभ उठाने जैसे खेती के मुद्दों पर त्वरित सेवाओं की जरूरत है। इसलिए, किसानों को सीएससी गेटवे के माध्यम से दी जाने वाली विभिन्न कृषि और संबद्ध क्षेत्र की सेवाओं पर एक अध्ययन किया गया।

इसका उद्देश्य किसानों द्वरा आवश्यक आई.टी. समर्थित किसानों द्वारा आवश्यक समर्थित कृषि सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं का अध्ययन करना; ग्रामीण स्तर पर किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीएससी / अन्य सेवा चैनलों के माध्यम से दी जाने वाली आई.टी. समर्थित कृषि और संबद्ध सेवाओं (ITeAS) की पहचान करना; और किसानों को महत्वपूर्ण सेवा उत्पादकों (कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्र, एनआईसी, राज्य स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के राज्य विभाग) के एक नेटवर्क के माध्यम से दी जानो वली महत्वपूर्ण आईटी समर्थित कृषि सेवा (ITeAS) को मानकीकृत करने के लिए एकीकृत तंत्र विकसित करना। अध्ययन तीन जिलों, अर्थात् आंध्र प्रदेश के नलगोंडा और विशाखापत्तनम तथा महाराष्ट्र के पुणे तक ही सीमित है, जहां सीएससी स्थापित हैं, और सितंबर 2014 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

आत्मा (एटीएमए) के तहत कृषिउद्यमियों के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए संस्थागत तंत्र विकसित हो - एक्शन रिसर्च

योजना के 2002 के दौरान शुरू की गई। एक्सटेंशन सुधारों के तहत, कृषिउद्यमियों द्वारा की गई विस्तार गतिविधियों के सेवा शुल्क की उपलब्धता के संवर्धन के लिए गतिविधियों के कैफेटेरिया के तहत एग्री क्लीनिक एवं कृषि व्यापार केन्द्रों की पहचान की गई। संशोधित एसी और एबीसी दिशा निर्देशों में एटीएमए के लोगों के साथ कृषिउद्यमियों की विस्तार गतिविधियों के एकीकरण के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। हालांकि कृषिउद्यमियों द्वारा क्षेत्र स्तर प्रतिक्रिया ने संकेत दिया है कि कृषिउद्यमियों और आत्मा के बीच संबंध बहुत कमजोर थे और आत्मा के अधिकारियों द्वारा समर्थन दिया गया।

एसी और एबीसी योजना अर्थात् जनता विस्तार के प्रयासों का सप्लीमेंट का मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, एटीएमए के तहत कृषिउद्यमियों के माध्यम से पीपीपी को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत तंत्र विकसित करने की मजबूत आवश्यकता है। इसके मद्देनज़र, एटीएमए और कृषिउद्यमियों के बीच संबंध की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए एक एक्शन रिसर्च शुरू किया गया; संयोजन के कमजोर और संभावित क्षेत्रों की पहचान करना; अनुसंधान कार्रवाई के लिए हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से पीपीपी मॉडल विकसित करना, जो संयोजन के कमजोर और संभावित क्षेत्रों के दर्शाने और प्रक्रिया दस्तावेज़ तथा लाभ बढ़ाने की संक्षिप्त नीति विकसित करे

संभावित परिणाम पीपीपी मॉडल हैं जो एटीएमए और कृषिउद्यमियों के बीच संबंध मजबूत बनाता है; स्केलिंग के लाभ के लिए संक्षिप्त नीति; सार्वजनिक और निजी विस्तार सेवा प्रदाताओं के बीच कन्वर्जेंस और तालमेल; निजी विस्तार सेवाओं के बेहतर विनियमन और किसानों के लाभ के लिए सार्वजनिक धन का बेहतर उपयोग।

कृषिउद्यमियों की पहचान और संवेदीकरण प्रगति में है।

पीजीडीएम (एबीएम) से समाचार

कृषि, खाद्य, कृषि इनपुट, कृषि बैंकिंग, खुदरा, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से संबंधित क्षेत्रों में करियर बनाने वाले शक्तिशाली उद्योगपति और तकनीकी प्रबंधक तैयार करने के उद्देश्य से मैनेज द्वारा मैनेजमेंट में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (एग्री बिजनेस मैनेजमेंट) रखा गया है।

एकबार फिर शत प्रतिशत प्लेसमेंट

इस साल भी मैनेज ने 100% (शत प्रतिशत) प्लेसमेंट हासिल किया। उनतीस कंपनियों परिसर का दौरा किया और 2012-14 बैच के सभी छात्रों की भर्ती किया। कृषि इनपुट, वित्त और बैंकिंग, कमोडिटी एक्सचेंजों, खुदरा और कंसल्टेंसी जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय के नियोक्ताओं ने प्रतिनिधित्व किया। नियुक्तियों की पेशकश औसतन रु.7.46 लाख की सीटीसी प्रतिवर्ष के साथ की थी।

समर इंटर्नशिप

2013-15 बैच के सभी छात्रों को ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के लिए रखा गया है जिसका उद्देश्य छात्रों को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में व्यावहारिक क्षेत्र अनुभव प्रदान करना है।

मेरिट मान्यता योजना (एमआरएस) का प्रारम्भ

योग्यत, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को को बढ़ावा देने के और उच्च प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत करने के लिए, मैनेज द्वारा पीजीडीएम (एबीएम) छात्रों के लिए एक योग्यता मान्यता योजना (एमआरएस) शुरू

की गई है। योग्यता प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार तिमाही में अव्वल रहने वाले छात्र, अलग पाठ्यक्रम, वर्ष के टॉपर और अधिकतम उपस्थिति के लिए को दिए गए।

2014 - लिट 'ओ' मिलेंज

22-23 मार्च, 2014 के दौरान मैनेज में एक लिटरेरी इवेंट 'लिट' ओ 'मिलेंज' आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शामिल थे:-

I) स्क्रीवेन - एक निबंध लेखन प्रतियोगिता,

II) रैंगल - एक संवाद प्रतियोगिता,

III) शीघ्र आशुभाषण - एक आशु इवेंट

IV) न्यूरॉन ट्विस्टर - एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता.

संकाय समाचार

मैनेज डा. सेंथिल विनयगम, निदेशक (कृषि विस्तार) को 14 अप्रैल 2014 को, अपने मूल विभाग में वापसी पर, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ विदाई देती है। मैनेज में डॉ. सेंथिल तीन साल की अवधि के लिए थे। मैनेज में वे, एलाइड एक्सटेंशन और जल/इनपुट उपयोग की दक्षता, PGDAEM कार्यक्रम समन्वय और कार्यकारी संपादक मैनेज जर्नल कृषि विस्तार प्रबंधन का कार्यभार संभाले हुए थे। वे अब ज्वार अनुसंधान निदेशालय (आईसीएआर), हैदराबाद, में प्रधान वैज्ञानिक (कृषि विस्तार) के रूप में कार्यभार संभाला है। मैनेज डॉ. सेंथिल को भविष्य के प्रयासों में सफलता की शुभकामनाएँ देता है।

मैनेज की वेवसाइट www.manage.gov.in देखें

मेनेज बुलेटिन का प्रकाशन :
श्री. बी. श्रीनिवास, आईएएस,
महानिदेशक, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान
(मैनेज) राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500030, भारत
दूरभाष : +91 (0) 4024016702 – 706
फैक्स - 91 (0) 4024015388

मुख्य संपादक : श्री. बी. श्रीनिवास, आईएएस
कार्यकारी संपादक : डॉ. वी.पी. शर्मा
संपादक : डॉ. लक्ष्मी मूर्ती